यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2019–22/110/2020 **दिनांक** : 04.07.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

कामगारों, श्रम संगठनों और हमारे अधिकारों पर बढ़ते हुए हमलों के विरूद्ध प्रबल विरोध

केन्द्र सरकार को कामगार–विरोधी नीतियों और कामगार वर्ग पर जारी हमलों के विरूद्ध केन्द्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर आज देशभर में अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाया गया। एआईबीईए के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में भी सभी जगह पर विरोध दिवस का आयोजन किया गया जिसको सफलता के विषय में विभिन्न इकाईओं से सूचनायें तथा तस्वीरें प्राप्त हो रही है। इसी क्रम में हम एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 28/210/2020/48 दिनांक 3.7.2020 का अनूदित सार अपनी सभी इकाईओं एवं सदस्यों के सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

एआईबीईए के ध्वज तले बैंक कर्मचारियों ने कामगारों, श्रम संगठनों और हमारे अधिकारों पर बढ़ते हमलों के विरूद्ध अपना प्रबल विरोध दर्ज कराया

इस दिवस पर बैज लगाए गए, प्लेकार्ड प्रदर्शित किए गए

आज, केन्द्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर, सम्पूर्ण कामगार वर्ग और श्रम संगठन आंदोलन ने श्रम संगठनों के अधिकारों पर तथा बड़े पैमाने पर कामगारों की नौकरियों तथा वेतन पर सरकार के बढ़ते हमलों के खिलाफ अपना विरोध, असंतोष, अस्वीकृति और रोष प्रकट किया। लॉकडाउन प्रतिबंधों और निषेधात्मक आदेशों के कारण, कामगारों की हमेशा की तरह व्यापक लामबंदी संभव नहीं थी लेकिन पूरे देश में, कामगारों का असंतोष दिखाई दे रहा था क्योंकि उन्होंने हर संभव तरीके से विरोध कार्यक्रमों में भाग लिया।

एआईबीईए के आह्वान पर, हमारे सदस्यों ने भी बैज पहनने, प्लेकार्ड प्रदशन, कुछ स्थानों पर स्थानीय प्रदर्शनों में भागीदारी, आदि के माध्यम से विरोध दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। सुबह से, हमारी इकाईयां कार्यक्रम में उनकी भागदारी की तस्वीरों को अग्रेषित कर रही हैं।

हम अपनी सभी इकाईओं और सदस्यों को धन्यवाद देते हैं कि वतमान कठिनाईयों, शाखाओं में सीमित उपस्थिति और सामाजिक दूरी प्रतिबंधों, आदि के बावजूद, हमारे सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग लिया। तस्वीरों से यह उल्लेखनीय था कि हमारे युवा सदस्यों ने उत्साह के साथ बैज धारण करने के कार्यक्रम में भाग लिया।

जारी पृष्ठ 2

केन्द्रीय श्रम संगठनों द्वारा जारी विज्ञप्ति इसके साथ संलग्न है।

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह...
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री

19 जुलाई, 2020 को अखिल भारतीय मांग दिवस की ओर बढ़ें – बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस एआईबीईए के आह्वान का इंतजार करें

प्रैस विज्ञप्ति

3 जुलाई, 2020 को केन्द्रीय श्रम संगठनों द्वारा देशव्यापी विरोध श्रम कानूनों में कठोर परिवर्तनों के विरूद्ध, सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईओं के निजीकरण के विरूद्ध और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के अधिकारों के लिए

केन्द्रीय श्रम संगठनों के ध्वज तले कामगार वर्ग, तथा क्षेत्रीय फैडरेशनों और एसोसिएशनों ने 3 जुलाई, 2020 को देशव्यापी विरोध दिवस मनाया, जो सरकार की कामगार–विरोधी, किसान–विरोधी, जन–विरोधी तथा राष्ट्र विरोधी नीतियों क असहयोग और अवज्ञा के संयुक्त संघर्ष के रूप में सभी कार्यस्थलों और केन्द्रों में, देशभर में व्यापक रूप से सफल रहा। कार्रवाई कार्यक्रम सभी राज्यों में सभी कार्यस्थलों, यूनियन कार्यालयों में, सड़कों और गलियों पर लगभग एक लाख स्थानों पर आयोजित किए गए।

दिल्ली में, औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे तथा एक कार्यक्रम श्रम शक्ति भवन के सामने हुआ जिसमें केन्द्रीय श्रम संगठनों के राष्ट्रीय नेता उपस्थित थे। जिन्होंने भाग लिया उनमें इंटक से अशोक सिंह, एटक के अमरजीत कौर, विद्या सागर गिरी, एचएमएस से हरभजन सिद्धू, सीटू से तपन सेन, हेमलता और देवरॉय, एआईयूटीयूसी से आर.के. शर्मा और चौरसिया, राजीव डिमरी और संतोष राय–एआईसीसीटीयू, सेवा से लता, यूटीयूसी से शत्रुजीत और एलपीएफ एवं एमइसी के नेता, बैंक और बीमा क्षेत्र के नेता शामिल थे। इंटक के अध्यक्ष संजीव रेड्डी, मनाली शाह–सेवा, अशोक घोष–यूटीयूसी और शिव शंकर और देवराजन ने अपने–अपने राज्यों में भाग लिया। कई क्षेत्रों से गिरफ्तारियों की सूचनायें मिलीं।

कुछ औद्योगिक इकाईओं के खुलने के साथ, सभी कामगारों को वापस नहीं लिया जा रहा है, केवल एक छोटा प्रतिशत नौकरियों में अपनी जगह वापस पा रहा है और वो भी कम वेतन पर और लॉकडाउन अवधि के वेतन का भुगतान करने से इंकार पर। इस प्रकार के रोजगार से इंकार और वेतन–कटोती के लिए दबाव डालने से एकजुटता से संघर्ष करना होगा।

बेरोजगार 14 करोड़ से अधिक हैं और यदि हम रोज कमाने वालों/ठेका/आकस्मिक को जोड़ते हैं, तो यह 24 करोड़ से अधिक है जो वर्तमान में आजीविका के बिना हैं। एमएसएमई स्वयं सूचित कर रहे हैं कि 30% से 35% इकाईयां अपनी गतिविधियों को शुरू की स्थिति में नहीं हो सकती हैं। अप्रैल तक बेरोजगारी दर 27% तक पहुंच गई थी। आईएलओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 40 करोड़ से अधिक लोग गहरी गरीबी में धकेले जायेंगे। प्रख्यात वैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि, कुपोषण बढ़ेगा, भूख से मौतें एक दैनिक वास्तविकता बन जायेगी, जिससे अवसाद का वास्तविक खतरा होगा और जिसके परिणामस्वरूप कामगारों में आत्महत्यायें होंगी। ये सभी मुद्दे कामगारों को नाराज कर रहे हैं।

जारी पृष्ठ 3

मोदी सरकार ने इंसानों और समाज के लिए चिकित्सा आपातकाल के रूप में लेने के बजाय प्रशासनिक मुद्दे के रूप में कोविड 19 की समस्या से बहुत असंवेदनशील तरीक से निपटा है। इसने लाखों कामगारों, किसानों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को भारी कष्ट पहुंचाया है। जबकि, सरकार केवल कॉर्पोरेटों और बड़े व्यवसायियों के साथ खड़ी रही, यूनियनों का आरोप है।

केन्द्रीय श्रम संगठनों ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश और थोक निजीकरण, मुख्य क्षेत्रों – इंडियन रेलवे, रक्षा, पोर्ट एवं डॉक, कोयला, एअर इंडिया, बैंकों, बीमा मे 100 प्रतिशत एफडीआई, अंतरिक्ष विज्ञान और परमाणु ऊर्जा आदि का निजीकरण, आत्म–निर्भर भारत के नारे से मुंह फेरते हुए देश के प्राकृतिक संसाधनों और व्यवसाय को हड़पने के लिए भारतीय और विदेशी ब्रांडों के कॉर्पोरेट्स के पक्ष में उपायों के लिए अपन विरोध को दोहराया।

48 लाख केन्द्र सरकार कर्मचारियों का डीए स्थिर रखने और 68 लाख पेंशनरों का डीआर स्थिर रखने क निर्णय, जिसका असर राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी पड़ रहा है, को सरकारी कर्मचारियों और केन्द्रीय श्रम संगठनों के प्रबल विरोध के बावजूद वापस नहीं लिया गया है। न ही सभी गैर–आय कर दाताओं के लिए रू0 7500/– के नकद अंतरण की मांग को स्वीकार किया गया है।

ऐसी सरकार जिसको कामगारों और लोगों के अधिकारों और बुनियादी अस्तित्व–अधिकारों के प्रति कोई सम्मान और चिंता नहीं है, वह किसी भी सहयोग के लायक नहीं है।

हम कामगारों/कर्मचारियों और श्रम संगठनों को एक दूसरे के साथ एकजुटता में रहने, सभी सावधानियां बरतते हुए बीमारी का एकजुटता से सामना करने, यूनियनोकरण, सामूहिक सौदेबाजी, सभ्य कार्य करने की स्थिति, वेतन और भविष्य की सुरक्षा आदि के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत है।

इस सरकार ने कामगारों और लोगों की बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के बारे में क्रूर असंवेदनशीलता प्रदर्शित की है। श्रम शक्ति भवन पर सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि इसका समर्थन और सहयोग नहीं किया जा सकता।

बाद में श्रम और रोजगार मंत्री श्री संतोष गंगवार और श्रम सचिव केन्द्रीय श्रम संगठनों के नेताओं से मिले और उनके ज्ञापन को स्वीकार किया।

इंटक | एटक | एचएमएस | सीटू | एआईयूटीयूसी

टीयूसीसी | सेवा | एआईसीसीटीयू | एलपीएफ | यूटीयूसी

साथी अमरजीत कौर, महामंत्री, एआईटीयूसी और साथी तपन सेन, महामंत्री, सीटू

दिल्ली में श्रम शक्ति भवन, श्रम मंत्री के कार्यालय के सामने
विरोध रैली में केन्द्रीय श्रम संगठनों के नेता